**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 835**

**दिनांक 21.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

विश्व शौचालय दिवस

**835. श्री विजय कुमार दूबेः**
**श्रीमती संध्या रायः**
**श्री धनुष एम॰ कुमारः**
**श्री मोहनभाई कुंडारियाः**
**श्री रेबती त्रिपुराः**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;
(ख) इस अवसर पर सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम का विषय क्या है;
(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है कि वर्ष 2030 तक सभी को स्वच्छ शौचालय मिले और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार ने खुले में शौच के उन्मूलन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने गांवों और जिलों में अभी भी खुले में शौच की प्रथा चल रही है; और
(च) उत्तर प्रदेश सहित देश में प्रत्येक घर में शौचालय के निर्माण के लिए सरकार द्वारा आगे किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, जल शक्ति**

**(श्री रतन लाल कटारिया)**

(क) और (ख) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 19 नवम्बर, 2019 को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2019 के आधार पर परिमाणात्मक और गुणात्मक स्वच्छता पैरामीटरों के आधार पर सर्वोच्च रैंक वाले राज्यों तथा जिलों को पुरस्कृत किया गया। स्वच्छता ही सेवा, 2019 में अपना योगदान देने के लिए विभिन्न संगठनों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया।

(ग) सरकार ने हाल ही में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस अर्थात् ओडीएफ के स्थायित्व और ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु 10 वर्ष की ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति (2019-2029) शुरू की है।

(घ) और (ड.) सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का प्रारंभ दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को किया था जिसका लक्ष्य देश में सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधाओं की पहुँच उपलब्ध कराकर 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत की स्थिति प्राप्त करना है। एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज जो 2.10.2014 को 38.7% था, बढ़कर 100% हो गया है और देश के सभी 5,99,963 गांवों ने स्वयं को पहले ही ओडीएफ घोषित कर दिया है। दिसंबर, 2018 में कराए गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) 2018-19 के अनुसार 93.1% ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

(च) एसबीएम की ऑनलाइन (जी)एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 100% स्वच्छता कवरेज प्राप्त कर लिया है। अब एसबीएम (जी) का फोकस ओडीएफ स्थायित्व पर है। सरकार ने आगे सभी राज्यों को सलाह दी है कि यह सुनिश्चित करें कि एसबीएम के अंतर्गत कोई भी पीछे (जी) छूट न जाए और छूट गए ग्रामीण परिवारों यदि कोई हों, तो उनकी पहचान करें और इस कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण में उनकी सहायता करें।